

आय कर आयुक्त, केरल

बनाम

श्रीमती पी. के. कोच्चाम्मू अम्मा पेरोक

23 सितंबर, 1980

[पी. एन. भगवती और ई. एस. वेंकटरमैया, न्यायाधिपतिगण]

जुर्माना, अधिरोपण- करदाता निर्धारण वर्ष 1964-65 के लिए आय के रिटर्न में पति या पत्नी और नाबालिग बच्चे की आय को शामिल करने में विफल रहा, हालांकि धारा 64(1) और (III) के तहत शामिल है- क्या विफलता पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 271 (1) (सी), के तहत जुर्माना लगता है, जेसा कि 1961 का असंशोधित नियम 12 (31-3-1972 से पहले) निर्धारित फॉर्म में कोई कॉलम प्रदान नहीं करता था- आयकर अधिनियम, 1961 धाराये 2(45), 4, 5, 64(1)(i) और (iii), 139 और 271(1)(सी) सपठित आयकर नियम, 1962 के नियम 12, का दायरा- शब्दों और वाक्यांशों "उसकी आय" का अर्थ.

प्रतिवादी निर्धारिती मैसर्स मालाबार टाइल वर्क्स और मैसर्स मालाबार प्लाइवुड वर्क्स की साझेदारी फर्मों में और उनके साथ उनके पति और नाबालिग बेटी सहित अन्य साझेदारों के साथ भागीदार था। निर्धारण वर्ष

1964-65 के लिए अपने रिटर्न में, जिसके लिए प्रासंगिक लेखा वर्ष 31 दिसंबर, 1963 को समाप्त होने वाला कैलेंडर वर्ष था, निर्धारिती ने साझेदारी फर्मों में अपने पति और नाबालिग बेटी के शेयरों का प्रतिनिधित्व करने वाली राशि को छोड़कर उसकी आय का रिटर्न दाखिल किया। हालाँकि, आयकर अधिकारी ने राशियाँ, अर्थात् रु. 59,506/- कर अधिनियम की धारा 271(1)(सी)के तहत सहायक अपीलीय आयुक्त को कार्यवाही हेतु प्रकरण संदर्भित किया, जिसने अपनी आय छुपाने के लिए निर्धारिती पर 7,000 रु. का जुर्माना लगाया। अपील में, न्यायाधिकरण ने आदेश को रद्द कर दिया और उच्च न्यायालय ने संदर्भ पर न्यायाधिकरण के आदेश की पुष्टि की। अतः राजस्व द्वारा विशेष अनुमति प्राप्त कर इस न्यायालय में अपील की गयी।

न्यायालय ने अपील खारिज करते हुए, अभिनिर्धारित किया:

(1) निर्धारिती, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अधिनियम की धारा 139 के तहत रिटर्न दाखिल करने के लिए निर्धारित फॉर्म 31 मार्च, 1972 से पहले अधिनियम के अध्याय V में "पति/पत्नी/नाबालिग बच्चे या किसी अन्य व्यक्ति को होने वाली आय" दिखाने के लिए अलग निर्दिष्ट कॉलम नहीं था, और तीन न्यायाधीशों के निर्णय के मद्देनजर 74 आई.टी.आर. 83 एससी में प्रकाशित, में यह नहीं कहा जा सकता है कि उसने दो साझेदारी फर्मों में अपने पति और नाबालिग बेटी के शेयरों का

प्रतिनिधित्व करने वाली रकम का खुलासा नहीं करके अपनी आय को छुपाया है। [788 बी]

(2) अधिनियम की धारा 271(1)(सी) के प्रयोजन के लिए "उसकी आय" शब्द "उसकी आय" है, जिसे निर्धारिती मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए प्रकट करने के लिए उत्तरदायी है और फिर भी ऐसा करने में विफल रहता है। एस के तहत आय की वापसी 139(1) की

(2) अधिनियम की धारा 271(1)(सी), के प्रयोजन के लिए "उसकी आय" शब्द "उसकी आय" है जिसे निर्धारिती मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए प्रकट करने के लिए उत्तरदायी है और फिर भी ऐसा करने में विफल रहता है। अधिनियम की धारा 139(1) के तहत आय की वापसी, राजस्व अधिकारियों को निर्धारिती पर कर का उचित मूल्यांकन करने में सक्षम बनाने के लिए दाखिल करना आवश्यक है। एक फोर्टियोरारी, यह इस प्रकार है कि निर्धारिती को रिटर्न में आय की प्रत्येक वस्तु का खुलासा करना होगा जो अधिनियम के धाराओ 4 और 5 के तहत उसके हाथों में कर लगाने के लिए उत्तरदायी है। [785 बी; एफ-एच]

(3) धारा 2(45) में "कुल आय" की परिभाषा, निस्संदेह धारा 5 को संदर्भित करता है, जो निर्धारित करता है कि निर्धारिती को अर्जित या उत्पन्न या निर्धारिती द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी आय लाभ और लाभ उसकी कुल आय में शामिल किए जाने के लिए उत्तरदायी होंगे,

लेकिन यह प्रावधान अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन है और इसलिए यदि अधिनियम के किसी भी प्रावधान द्वारा किसी अन्य व्यक्ति की आय को निर्धारिती की कुल आय की गणना में शामिल करने के लिए घोषित किया जाता है, तो ऐसी आय अधिनियम की धारा 4 के तहत कर योग्य कुल आय का हिस्सा बनेगी। धारा 64(1) एक ऐसा प्रावधान है जो निर्धारिती की कुल आय की गणना में कुछ अन्य व्यक्तियों की आय को शामिल करने का प्रावधान करता है। [785 एफ-एच]

धारा 64(1) यह स्पष्ट करती है कि यद्यपि किसी साझेदारी फर्म, जिसमें करदाता भागीदार है, के मुनाफे में पति या पत्नी या नाबालिग बच्चे का हिस्सा निर्धारिती की आय नहीं है, बल्कि ऐसे पति या पत्नी या नाबालिग बच्चे की आय है। निर्धारिती की कुल आय की गणना में शामिल होने के लिए उत्तरदायी है और यह निर्धारिती के हाथों कर के लिए निर्धारण योग्य होगा। कर के दायरे में आने वाले निर्धारिती की कुल आय में साझेदारी फर्म के मुनाफे में पति या पत्नी और नाबालिग बच्चे के शेयरों का प्रतिनिधित्व करने वाली राशि शामिल होगी। स्पष्ट रूप से धारा 139 की उपधारा (1) में "उसकी आय" शब्द आय की प्रत्येक वस्तु को शामिल करना चाहिए जो अधिनियम के तहत मूल्यांकन योग्य उसकी कुल आय बनाती है। साझेदारी फर्म के मुनाफे में पति या पत्नी और नाबालिग बच्चे के शेयरों का प्रतिनिधित्व करने वाली राशि कर निर्धारण के उद्देश्य से

"उसकी आय" का हिस्सा होगी और उसे उसके द्वारा दाखिल आय रिटर्न में दिखाना होगा। [786 बी-डी]

(4) यह सच है कि आयकर नियम, 1962 के नियम 12 द्वारा निर्धारित रिटर्न का फॉर्म, जो संबंधित मूल्यांकन वर्ष के दौरान लागू था, में पति या पत्नी और नाबालिग बच्चे की आय दिखाने के लिए कोई अलग कॉलम नहीं था। निर्धारिती की कुल आय में शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन इसमें यह कहते हुए एक नोट शामिल था कि यदि किसी अन्य व्यक्ति की आय, अन्य बातों के साथ, धारा 64 के प्रावधानों के तहत निर्धारिती की कुल आय में शामिल है, तो ऐसी आय इसे उचित शीर्ष के अंतर्गत रिटर्न में भी दर्शाया जाना चाहिए। इस नोट में स्पष्ट रूप से निर्धारिती को आय के उचित शीर्ष, अर्थात् "व्यापार या पेशे के लाभ और लाभ" के तहत रिटर्न में दो साझेदारी फर्म के मुनाफे में निर्धारिती के पति और नाबालिग बेटी के शेयरों का प्रतिनिधित्व करने वाली राशि दिखाने की आवश्यकता है। हालाँकि, निर्धारिती अपने द्वारा प्रस्तुत रिटर्न में इन राशियों का खुलासा करने में विफल रही और यह स्पष्ट रूप से धारा 139 उपधारा (1) द्वारा लगाए गए दायित्व का उल्लंघन था। निर्धारिती को निर्धारित प्रपत्र में अपनी आय का रिटर्न प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। इस तर्क को स्वीकार करने के लिए कि नोट के बावजूद करदाता अभी भी दो साझेदारी फर्म में अपने पति और नाबालिग बेटी के शेयरों की रकम को रिटर्न में दिखाने के लिए उत्तरदायी नहीं थी, नोट को निरर्थक और

अर्थहीन बना देगा और इसे डेड-लेट में बदल देगा और यह निर्माण के सभी मान्यता प्राप्त सिद्धांतों के विपरीत होगा। निर्धारिती आय की इस मद को छिपाने का दोषी था जो स्पष्ट रूप से धारा 271 उप. (1) खंड (सी) की प्रयोज्यता को आकर्षित करता था। (786 जी-787 डी]

वी.डी.एम.आरएम.एम.आरएम. मुथैया चेट्टियार बनाम आयकर आयुक्त, 74 आईटीआर 183 (एससी), संदेह व्यक्त किया गया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 1086/1973

उच्च न्यायालय, केरल के टी.आई.टी. सन्दर्भ क्रमांक 91/69 में निर्णय और आदेश दिनांकित 8-12-1971 से विशेष अनुमति द्वारा अपील।

एस. सी. मनचंदा और मिस ए. सुभाषिनी; अपीलकर्ताओं के लिए।

के. टी. हरींद्रनाथ और टी. टी. कुन्धिकन्नन; प्रतिवादी के लिये।

न्यायालय का निर्णय भगवती न्यायाधिपति द्वारा सुनाया गया।

यह अपील राजस्व अधिकारियों द्वारा निर्धारिती पर जुर्माना लगाने के लिए शुरू की गई कार्यवाही से उत्पन्न हुई है। निर्धारिती एक महिला है और मूल्यांकन वर्ष 1964-65 के दौरान, जिसके लिए प्रासंगिक लेखा वर्ष 31 दिसंबर, 1963 को समाप्त हुआ कैलेंडर वर्ष था, निर्धारिती दो साझेदारी फर्मों मालाबार टाइल वर्क्स और मैसर्स मालाबार प्लाइवुड वर्क्स में भागीदार थी, और उसके साथ उसके पति और नाबालिग बेटी सहित अन्य साझेदार भी थे। निर्धारिती ने आकलन वर्ष 1964-65 के लिए आय का रिटर्न

दाखिल किया, जिसमें रु. 4754 रु संपत्ति से आय के रूप में और 4748 रु अन्य स्रोतों से आय के रूप में करदाता ने आइटम (बी) के सामने "व्यापार और पेशे के लाभ और लाभ" कॉलम के तहत रिटर्न में कहा, जिसे दिखाने के लिए एक पंजीकृत फर्म के मुनाफे में हिस्सेदारी की आवश्यकता होती है "कृपया फर्मों की फाइलों से मालाबार टाइल वर्क्स और मालाबार प्लाईवुड वर्क्स। हालाँकि, निर्धारिती ने रिटर्न में मैसर्स मालाबार टाइल वर्क्स और मैसर्स मालाबार प्लाईवुड वर्क्स की फर्मों में अपने पति और नाबालिग बेटी के शेयरों का प्रतिनिधित्व करने वाली राशि नहीं दिखाई। हालांकि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 64 उप-धारा (1) खंड (i) और (iii) के तहत निर्धारिती की कुल आय की गणना में स्पष्ट रूप से शामिल थे। मूल्यांकन करते समय आयकर अधिकारी ने निर्धारिती के मूल्यांकन में इन दो फर्मों के मुनाफे में निर्धारिती के पति और नाबालिग बेटी के शेयरों का प्रतिनिधित्व करने वाली राशियों को शामिल किया और इन राशियों को मिलाकर 59,506 रु की कुल आय पर निर्धारिती पर कर लगाया गया। चूंकि निर्धारिती ने अपने द्वारा प्रस्तुत रिटर्न में इन राशियों को अपनी कुल आय का हिस्सा नहीं दिखाया था, हालांकि वे धारा 64, उप-धारा (1) खंड (i) और (iii) के तहत उसकी कुल आय में स्पष्ट रूप से शामिल थे। आयकर अधिकारी का विचार था कि निर्धारिती ने अपनी आय के स्रोत के विवरणों को छुपाया था और खुद को धारा 271 उप-धारा (1) खंड (सी) के तहत दंड के लिए उत्तरदायी बना दिया। और चूंकि निर्धारिती पर लगाया

जाने वाला न्यूनतम जुर्माना रु. 1000 था। उन्होंने मामले को सहायक अपीलीय आयुक्त के पास भेज दिया, जिन्होंने धारा 274 के तहत नोटिस जारी किया और निर्धारिती को सुनने के बाद, रुपये 1000 का जुर्माना लगाया। निर्धारिती ने जुर्माना लगाने के आदेश के खिलाफ न्यायाधिकरण में अपील की और अपील के समर्थन में निर्धारिती की ओर से दिए गए तर्कों में से एक यह था कि शेयरों का प्रतिनिधित्व करने वाली राशि को अपने रिटर्न में दिखाने के लिए निर्धारिती की कोई बाध्यता नहीं थी। दो फर्मों में उसके पति और नाबालिग बेटी की और तदनुसार उसके द्वारा अपनी आय के विवरण को छुपाया नहीं गया ताकि धारा 271 उप-धारा (1) खंड (सी) के तहत जुर्माना लगाया जा सके। न्यायाधिकरण ने निर्धारिती के इस तर्क को स्वीकार कर लिया और माना कि धारा 271 उप-धारा (1) खंड (सी) को केवल तभी लागू किया जा सकता है जब "निर्धारिती द्वारा उसकी आय का विवरण" और संदर्भित शब्द "उसकी आय" को छुपाया गया हो। केवल स्वयं निर्धारिती की आय होनी चाहिए न कि किसी अन्य व्यक्ति की आय, जो धारा 64 उप-धारा (1) खंड (i) और (iii) के कारण निर्धारिती की आय में शामिल होने के लिए उत्तरदायी हो सकती है। न्यायाधिकरण ने तदनुसार माना कि करदाता द्वारा अपने रिटर्न में दो फर्मों में अपने पति और नाबालिग बेटी के शेयरों का प्रतिनिधित्व करने वाली रकम का खुलासा करने में चूक या विफलता, जो उसकी आय का हिस्सा है, को धारा 271 की उपधारा (1) खंड (सी) के तहत जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है और



इस दृष्टि से, न्यायाधिकरण ने अपील की अनुमति दी और जुर्माना लगाने के आदेश को रद्द कर दिया। इसके कारण राजस्व द्वारा संदर्भ के लिए एक आवेदन दाखिल किया गया और आवेदन पर, न्यायाधिकरण ने उच्च न्यायालय की राय के लिए कानून के निम्नलिखित प्रश्न को संदर्भित किया:

"क्या तथ्यों और मामले की परिस्थितियों के आधार पर, न्यायाधिकरण धारा 271(1)(सी) के तहत लगाए गए जुर्माने को रद्द करने में कानूनन सही है?"

उच्च न्यायालय ने यह विचार किया कि धारा 271 उप-धारा (1) खंड (सी) में प्रयुक्त शब्द "उसकी आय" थे और दोनों फर्मों में निर्धारिती के पति और नाबालिग बेटी के शेयरों का प्रतिनिधित्व करने वाली राशि को निर्धारिती की आय के बारे में नहीं कहा जा सकता है हालाँकि उसकी कुल आय की गणना में ये राशियाँ धारा 64 उप-धारा (1) खंड (i) और (iii) के कारण शामिल होने के लिए उत्तरदायी थीं और इसलिए, निर्धारिती के बारे में यह नहीं कहा जा सकता था उसने अपनी आय छुपा ली जब उसने अपने द्वारा जमा किए गए रिटर्न में इन राशियों को अपनी आय का हिस्सा नहीं बताया। तदनुसार, उच्च न्यायालय ने उसके पक्ष में संदर्भित प्रश्न का उत्तर दिया।

इस अदालत का एक निर्णय है जो सीधे मुद्दे पर है और यह राजस्व के खिलाफ इस अपील में उत्पन्न होने वाले प्रश्न के निर्धारण का निष्कर्ष निकालता है लेकिन इससे पहले कि हम उस निर्णय का उल्लेख करें, हम पहले शुद्ध व्याख्या के मामले के रूप में सिद्धांत पर प्रश्न की जांच शुद्ध व्याख्या द्वारा कर सकते हैं। धारा 271 उप-धारा (1) खंड (सी) एक निर्धारिती पर जुर्माना लगाने का प्रावधान करता है यदि अन्य बातों के साथ-साथ यह पाया जाता है कि निर्धारिती ने "अपनी आय" का विवरण छुपाया है। सवाल यह है कि इस दंडात्मक प्रावधान में आने वाले "उसकी आय" शब्दों का दायरा और सामग्री क्या है। क्या वे केवल स्वयं निर्धारिती की आय का उल्लेख करते हैं या क्या वे दूसरों की आय भी लेते हैं जो अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के कारण निर्धारिती की कुल आय की गणना में शामिल होने के लिए उत्तरदायी है, जैसे कि धारा 64 की उपधारा (1) खंड (i) और (iii)? इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि "उसकी आय" क्या है जिसे निर्धारिती छिपाने के लिए मूल्यांकन के उद्देश्य से प्रकट करने के लिए उत्तरदायी है, केवल वही हो सकता है जिसका खुलासा करने के लिए कोई बाध्य है और फिर भी वह ऐसा करने में विफल रहता है। धारा 139 एक निर्धारिती द्वारा आय का रिटर्न दाखिल करने का प्रावधान करती है और इस धारा की उपधारा (1) में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसकी पिछले वर्ष के दौरान कुल आय उस अधिकतम राशि से अधिक है जो आयकर के दायरे में नहीं आती है,

उसे एक विवरण प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित प्रपत्र में अपनी आय की वापसी और निर्धारित तरीके से सत्यापित, और ऐसे अन्य विवरण निर्धारित करना जो निर्धारित किया जा सकता है। राजस्व अधिकारियों को निर्धारिती पर कर का उचित मूल्यांकन करने में सक्षम बनाने के लिए आय का रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है। इसलिए इसे एक शर्त का पालन करना चाहिए कि -करदाता को रिटर्न में आय की हर उस वस्तु का खुलासा करना होगा जिस पर उसकी कुल आय के हिस्से के रूप में कर लगाया जा सकता है। आयकर का शुल्क निर्धारिती की कुल आय पर धारा 4 द्वारा लगाया जाता है, और 'कुल आय' को धारा 2 उप-धारा (45) में परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है "धारा 5 में निर्दिष्ट आय की कुल राशि की गणना अधिनियम में निर्धारित तरीके की गई है", इसमें कोई संदेह नहीं है कि धारा 2 उप-धारा (45) में 'कुल आय' की परिभाषा धारा 5 को संदर्भित करती है और यह बाद वाला प्रावधान बताता है कि सभी आय लाभ और लाभ अर्जित या निर्धारिती को प्राप्त हुए या 'द्वारा या' प्राप्त किए गए। निर्धारिती की ओर से उसकी कुल आय में शामिल होने के लिए उत्तरदायी होगा, लेकिन यह प्रावधान 'अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन है और इसलिए यदि किसी अन्य व्यक्ति की आय को अधिनियम के किसी प्रावधान द्वारा निर्धारिती की कुल आय को गणना में शामिल करने के लिए घोषित किया जाता है ऐसी आय अधिनियम की धारा 4 के तहत कर योग्य कुल आय का हिस्सा होगी। अब, धारा 64 उप-धारा (1) एक ऐसा

प्रावधान है जो एक निर्धारिती की कुल आय की गणना में कुछ अन्य व्यक्तियों की आय को शामिल करने का प्रावधान करता है। इस उप-धारा के खंड (i) और (iii) में प्रावधान है कि एक निर्धारिती की कुल आय की गणना में ऐसी सभी ऐसी आय जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे करदाता के पति या पत्नी की किसी ऐसे व्यवसाय को चलाने वाली फर्म में साझेदारी से उत्पन्न होती है को शामिल किया जायेगा, जिसमें ऐसा व्यक्ति भागीदार है और साथ ही ऐसे करदाता के नाबालिग बच्चे के प्रवेश से साझेदारी फर्म के लाभ से उत्पन्न होती है। इस प्रावधान से यह स्पष्ट है कि हालांकि साझेदारी-फर्म के मुनाफे में पति या पत्नी या नाबालिग बच्चे का हिस्सा, जिसमें निर्धारिती एक भागीदार है, निर्धारिती की आय नहीं है, लेकिन ऐसे पति या पत्नी या नाबालिग बच्चे की आय है, यह निर्धारिती की कुल आय की गणना में शामिल होने के लिए उत्तरदायी है और यह निर्धारिती के हाथों कर के लिए निर्धारण योग्य होगा। कर के दायरे में आने वाले निर्धारिती की कुल आय में साझेदारी फर्म के मुनाफे में पति/पत्नी और नाबालिग बच्चे के शेयरों को दर्शाने वाली राशि शामिल होगी। यदि यह सही कानूनी स्थिति है, तो इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि निर्धारिती को अपने द्वारा प्रस्तुत रिटर्न में, साझेदारी फर्म के मुनाफे में पति या पत्नी और नाबालिग बच्चे के शेयरों का प्रतिनिधित्व करने वाली सभी राशियों का खुलासा करना होगा, जिसमें वह भागीदार है। चूंकि वे कर के दायरे में आने वाली उसकी कुल आय का हिस्सा हैं। धारा 139

उप-धारा (1) में "उसकी आय" शब्द में आय की प्रत्येक वस्तु शामिल होनी चाहिए जो अधिनियम के तहत मूल्यांकन योग्य उसकी कुल आय बनाती है। साझेदारी फर्म के मुनाफे में पति या पत्नी और नाबालिग बच्चे के शेयरों का प्रतिनिधित्व करने वाली राशि कर निर्धारण के उद्देश्य से "उसकी आय" का हिस्सा होगी और उसे उसके द्वारा दाखिल आय रिटर्न में दिखाना होगा।

तब निर्धारिती ने तर्क दिया कि आय का रिटर्न जो धारा 139 उप-धारा (1) के तहत उसके द्वारा निर्धारित प्रपत्र में रिटर्न दाखिल करना आवश्यक था और रिटर्न का प्रपत्र निर्धारित था, आयकर नियम, 1962 के नियम 12 के अनुसार पति/पत्नी और नाबालिग बच्चे की आय दिखाने के लिए कोई कॉलम नहीं था। धारा 64 उप-धारा (1) खंड (i) और (iii) के तहत निर्धारिती की कुल आय में शामिल होने के लिए उत्तरदायी है और इसलिए उसके द्वारा दाखिल रिटर्न में इस आय का खुलासा करने के लिए निर्धारिती पर कोई दायित्व नहीं था। हमारी राय में यह विवाद भी भ्रामक और उचित होने के कारण अस्वीकार किये जाने योग्य है। यह सच है कि संबंधित मूल्यांकन वर्ष के दौरान लागू नियम 12 द्वारा निर्धारित रिटर्न के फॉर्म में निर्धारिती की कुल आय में शामिल होने के लिए उत्तरदायी पति या पत्नी और नाबालिग बच्चे की आय दिखाने के लिए कोई अलग कॉलम नहीं था। लेकिन इसमें एक नोट शामिल था जिसमें कहा गया था कि यदि किसी अन्य व्यक्ति की आय धारा 64 के प्रावधानों के तहत निर्धारिती की

कुल आय में शामिल है, तो ऐसी आय को उचित शीर्ष के तहत विवरणी में भी दिखाया जाना चाहिए। इस नोट में स्पष्ट रूप से निर्धारिती को आय के उचित शीर्ष, अर्थात् "व्यवसाय या पेशे के लाभ और लाभ" के तहत विवरणी में निर्धारिती के पति और नाबालिग बेटी के दोनो साझेदार फर्मों के लाभ में शेयरों का प्रतिनिधित्व करने वाली राशि दिखाने की आवश्यकता है। लेकिन फिर भी, निर्धारिती अपने द्वारा प्रस्तुत रिटर्न में इन राशियों का खुलासा करने में विफल रही और इसलिए स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से धारा 139 उप-धारा (1) द्वारा लगाए गए दायित्व का उल्लंघन था, जिसमें निर्धारिती को अपनी आय का विवरण निर्धारित- प्रपत्र में प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी। यह देखना मुश्किल है कि विवरणी के निर्धारित फॉर्म में नोट को निर्धारिती द्वारा कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है और वह यह तर्क दे सकती है कि नोट के बावजूद, वह अपने विवरणी में अपने पति और नाबालिग बेटी के दो साझेदारी फर्मों में शेयरों का प्रतिनिधित्व करने वाली राशि दिखाने के लिए उत्तरदायी नहीं थी। निर्धारिती का तर्क, यदि स्वीकार कर लिया जाता है, तो नोट निरर्थक और निरर्थक हो जाएगा और इसे मृत पत्र में बदल दिया जाएगा और यह निर्माण के सभी मान्यता प्राप्त सिद्धांतों के विपरीत होगा। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि निर्धारिती अपने रिटर्न में दो साझेदारी फर्मों में अपने पति और नाबालिग बेटी के शेयरों का प्रतिनिधित्व करने वाली राशि दिखाने के लिए बाध्य थी और ऐसा करने में विफल रहने पर, वह आय की इस मद को छिपाने की

स्पष्ट रूप से दोषी थी, जिसने धारा 271 उप-धारा (1) खंड (सी) की प्रयोज्यता को आकर्षित किया।

यह स्पष्ट है कि इस दृष्टिकोण से निर्धारिती पर जुर्माना लगाने के आदेश को बरकरार रखना होगा लेकिन वी.डी.एम.आरएम.एम.आरएम. मुथैया चेट्टियार बनाम आयकर आयुक्त मद्रास (1) में इस न्यायालय का एक निर्णय है जो हम पर बाध्यकारी है और जहां हमने पाया कि इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की एक पीठ ने एक अलग दृष्टिकोण अपनाया है। इस मामले में यह माना गया था कि भले ही रिटर्न के रूप में कोई मुद्रित निर्देश थे, जिसमें निर्धारिती को अपनी पत्नी और नाबालिग बच्चे द्वारा उस फर्म से प्राप्त आय का खुलासा करने की आवश्यकता होती है, जिसमें निर्धारिती एक भागीदार था। विवरणी में किसी भी शीर्ष की अनुपस्थिति जिसके तहत पत्नी या नाबालिग बच्चे की आय दिखाई जा सकती है, आय की इस मद का खुलासा करने के लिए निर्धारिती पर कोई दायित्व नहीं है, निर्धारिती को भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 34(1)(ए) के अर्थ के अंतर्गत उसके मूल्यांकन के लिए आवश्यक भौतिक तथ्य पूरी तरह से और सही मायने में खुलासा करने में असफल या छोड़ा हुआ नहीं माना जा सकता है। इस मामले का फैसला करने वाले विद्वान न्यायाधीशों के प्रति अत्यंत सम्मान के साथ, हमें नहीं लगता कि, पहले से ही चर्चा किए गए कारणों के कारण, कि यह निर्णय इस विषय पर सही कानून निर्धारित करता है, और यदि ऐसा नहीं होता तो 1 अप्रैल

1972 से नियम 12 द्वारा निर्धारित रिटर्न के फॉर्म में संशोधन किया गया है और तब से, अधिनियम के अध्याय V में संदर्भित पति/पत्नी/नाबालिग बच्चे या किसी अन्य व्यक्ति को होने वाली आय" को दिखाने वाला वाला एक अलग कॉलम है, उस कॉलम के तहत अलग से दिखाया जाना चाहिए और परिणामस्वरूप यह तर्क देने की कोई गुंजाइश नहीं है कि निर्धारिती ऐसी आय को अपने दाखिल किये जाने वाली विवरण में बताये जाने की बाध्य नहीं है। हम वर्तमान मामले को एक बड़ी पीठ के पास भेज देते, लेकिन हम ऐसा करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं क्योंकि 1 अप्रैल 1972 से लागू विवरणी के रूप में संशोधन के मद्देनजर प्रश्न अब अकादमिक हो गया है। इसलिए हम मुथैया चेट्टियार के मामले में इस निर्णय का पालन करेंगे, जो एक निर्णय है इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय हमारे लिए बाध्यकारी है, और उस निर्णय के बाद, हम मानते हैं कि निर्धारिती के बारे में यह नहीं कहा जा सकता है कि उसने अपने पति और नाबालिग बेटी के दो साझेदारी फर्मों में शेयरों का प्रतिनिधित्व करने वाली रकम का खुलासा रिटर्न में न करके अपनी आय छुपाई है।

हम तदनुसार अपील को खारिज करते हैं, लेकिन वर्तमान मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में, हम सोचते हैं कि लागत का उचित क्रम यह होगा कि प्रत्येक पक्ष को अपनी लागत वहन करनी चाहिए और भुगतान करना चाहिए।



एस.आर.

अपील खारिज की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सुवास की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता नृपेन्द्र सिनसिनवार द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।